मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

जाने-माने स्कॉलर प्रो. विभूति पटेल का जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 'जेंडर रिस्पोंसिव बजटिंग इन इंडिया' पर विशेष व्याख्यान

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र (एसएनसीडब्ल्यूएस) ने 28 जुलाई, 2025 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और जेंडर अध्ययन विशेषज्ञ प्रो. विभूति पटेल द्वारा एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। प्रो. विभूति पटेल वर्तमान में इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली में विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 'टू डेकेड्स ऑफ़ जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग इन इंडिया (2005-2025)' शीर्षक वाला यह विशेष व्याख्यान, पिछले दो दशकों में अपनी राजकोषीय नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करने की भारत की यात्रा पर प्रकाश डालता है। यह व्याख्यान वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया।

व्याख्यान की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र की मानद निदेशक प्रो. निशात जैदी ने की। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. अदफर राशिद शाह ने विषय का परिचय और स्वागत वक्तव्य दिया तथा प्रो. जैदी ने उद्घाटन भाषण दिया और वक्ताओं का प्रतिभागियों से परिचय कराया।

प्रो. विभूति पटेल ने 2005 में इसे अपनाए जाने के बाद से भारत में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) के विकास का वर्णन किया। अपने व्यापक शोध के आधार पर, उन्होंने महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि जैसी प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, साथ ही कार्यान्वयन में कमियों और बेहतर जेंडर-विभाजित आंकड़ों की आवश्यकता जैसी लगातार चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जेंडर बजटिंग न्याय के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राजकोषीय नीतियाँ महिलाओं और हाशिये के समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करें ताकि एक समतापूर्ण समाज को बढ़ावा मिल सके।

व्याख्यान में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार जैसे क्षेत्रों पर जीआरबी के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया गया, जिससे इसकी सफलताओं और कमियों के बारे में जानकारी मिली। प्रो. पटेल ने जीआरबी को मज़बूत करने और इसे 2030 तक भारत के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए दूरदर्शी रणनीतियों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जीआरबी के समन्वय और मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालयों के भीतर 'जेंडर बजटिंग सेल' जैसी संस्थागत संरचनाओं के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जीआरबी केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी मंत्रालयों को जेंडर-विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है।

यह व्याख्यान एसएनसीडब्ल्यूएस की स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस व्याख्यान ने लैंगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आलोचनात्मक चर्चा को बढ़ावा देकर "भारत कोकिला" सरोजिनी नायडू की विरासत का सम्मान किया। इस कार्यक्रम ने एडवोकेसी और अनुसंधान के अलावा लैंगिक समानता और समावेशी नीति निर्माण पर अकादमिक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एसएनसीडब्ल्यूएस की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

अपने समापन भाषण में, प्रो. निशात जैदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जेंडर-संवेदनशील बजट, बजट प्रक्रिया के सभी चरणों में लैंगिक दृष्टिकोण को समाहित करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर तथा सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करके उन्हें सशक्त बनाता है।

इसके बाद हुए आकर्षक प्रश्नोत्तर सत्र ने गतिशील चर्चाओं को जन्म दिया, जिसमें प्रतिभागियों के विविध दृष्टिकोणों ने व्याख्यान को समृद्ध बनाया और जेंडर-केंद्रित नीति-निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक और समावेशी वातावरण का निर्माण किया। विभिन्न विषयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षाविदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से जीवंत चर्चाओं और विविध दृष्टिकोणों ने व्याख्यान को समृद्ध बनाया और एक समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया।

व्याख्यान का समापन एम.ए. जेंडर अध्ययन तृतीय सेमेस्टर की छात्रा ज़ोयबा द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

प्रो. साइमा सईद
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी